<u>लोकसभा</u>

तारांकित प्रश्न संख्या *84

17 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

***84. श्री के. एन. रामचन्द्रनः**

श्री प्रह्लाद जोशीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश में सेलम और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों सहित विभिन्न सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार का कार्य आरंभ किया गया है/आरंभ किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ आधुनिकीकरण की अनुमानित लागत एवं आवंटित धनराशि संयंत्र-वार कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने सभी सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों को उनके आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार कार्यक्रमों के तहत ऊर्जा दक्षता एवं उत्सर्जन की कमी संबंधी प्रावधान करने का निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ग्लोबल एन्वायरनमेंट फैसिलिटी के माध्यम से संयंत्र क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता एवं उत्सर्जन कमी को हासिल करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक संयंत्र के आधुनिकीकरण के कार्य को आरंभ और पूरा करने की संभावित तिथि क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त संयंत्रों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार और आधुनिकीकरण करने तथा राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को कार्यान्वित करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ): एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण" के बारे में श्री के.एन.रामचन्द्रन एवं श्री प्रहलाद जोशी, संसद सदस्य द्वारा लोक सभा में दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर देने के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *84 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के नाते सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिए आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय व्यक्तिगत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा वाणिज्यिक सोच-विचारों और बाजार गतिशीलता के आधार पर लिया जाता है। दो प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने अपने इस्पात संयंत्रों में आधुनिकीकरण और विस्तारण का कार्य हाल ही में शुरू किया है। इसमें भिलाई (छत्तीसगढ़), बोकारो (झारखंड), राउरकेला (ओडिशा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तथा बर्नपुर (पश्चिम बंगाल), सेलम (तमिलनाडु) में स्थित सेल के इस्पात संयंत्र और विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में स्थित आरआईएनएल के इस्पात संयंत्र शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए वित्त-पोषण, संबंधित कंपनी द्वारा स्वयं के संसाधनों से और/या बैंक/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण से किया जाता है।

सेल के संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए सांकेतिक निवेश 61,870 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, खानों के विकास और विस्तार के लिए 10,264 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सेल के आधुनिकीकरण और विस्तार योजना का संयंत्र-वार ब्यौरा निम्नवत् है:-

संयंत्र	**क्रूड इस्पात क्षमता एमटीपीए में (मिलियन टन प्रतिवर्ष)**		**अनुमोदित लागत करोड़ रुपये में (नेट सेनवाट)**
	विस्तार पूर्व	**विस्तार के पश्चात्**	
भिलाई इस्पात संयंत्र	3.93	7.0	17,266
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	1.8	2.2	2,875
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1.9	4.2	11,812
बोकारो इस्पात संयंत्र	4.36	4.61	6,325
इस्को इस्पात संयंत्र	0.5	2.5	16,408
सेलम इस्पात संयंत्र	-	0.18	1,902
विभिन्न संयंत्रों में रख-रखाव योजना	-	-	5,282

आरआईएनएल ने 12,291 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अप्रैल, 2015 में विजाग इस्पात संयंत्र की तरल इस्पात क्षमता को 3 एमटीपीए से 6.3 एमटीपीए तक दोगुना करने के लिए विस्तारण कार्य पूरा कर लिया है। इसके अलावा, आरआईएनएल ने तरल इस्पात क्षमता को 4000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1 एमटीपीए अर्थात् 6.3 एमटीपीए से 7.3 एमटीपीए तक बढ़ाने के लिए, मुख्य उपस्कर को मजबूत बनाए रखने हेतु ब्लास्ट फर्नेस, स्टील मेल्टिंग शॉप कंवरटर्स और सिंटर प्लांट जैसी मौजूदा मुख्य उत्पादन सुविधाओं का आधुनिकीकरण प्रारंभ किया। सभी आधुनिकीकृत इकाइयाँ प्रचालन में है।

(ग) और (घ): देश में इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार कार्यक्रम इकाइयों को ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने की परिकल्पना से किया जाता है। किसी भी इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार परियोजना के लिए, सरकार के संबंधित एजेंसियों/विभागों से पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त की जाती है। ऊर्जा-दक्षता और उत्सर्जन में कमी का प्रावधान पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया में अंतर्निहित है।

सेकेंडरी इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा प्रभावी उत्पादन के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वैश्विक पर्यावरण सुविधा के जरिए 34 मॉडल इकाइयों में, ऊर्जा प्रभावी और उत्सर्जन प्रौद्योगिकी प्रारंभ की गई हैं।

(ङ): अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियाँ वाणिज्यिक सोच-विचारों और बाजार गतिशीलता के आधार पर नियमित रूप से अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा परियोजनाओं में समय-समय पर पूँजीगत निवेश करती है।

*****